## सम्पादकीय

### नागरिकता संशोधन कानून पर अमेरिका की बयानबाजी आपत्तिजनक

देश में लागू हुए नागरिकता संशोधन विधेयक (सीएए) को लेकर अमेरिका का एक बयान सामने आया है। अमेरिका विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि अमेरिकी सरकार सीएए को लेकर चिंतित है। अमेरिका का सीएए पर ये स्टेंड आपत्तिजनक है। हालांकि भारत सरकार ने इसको आंतरिक मामला बताकर अपनी आपत्ती भी जता दी है फिर भी केन्द्र सरकार के विदेश मंत्रालय को और अधिक कड़े शब्दों में इसकी भर्त्सना करनी चाहिए क्योंकि अमेरिका हमारे देश में लागू होने वाले कानूनों को लेकर इस तरह की बातें क्यों करे? नागरिकता संशोधन कानून पर अमेरिका के बयान को लेकर भारत का जवाब सामने आया है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रंधीर जायसवाल ने कहा- नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 भारत का आंतरिक मामला है और इस पर अमेरिका का बयान गलत है। दरअसल, इस कानून को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा- हम 11 मार्च को आए सीएए के नोटिफिकेशन को लेकर चिंतित हैं। इस कानून को कैसे लागू किया जाएगा हम इसकी करीब से निगरानी कर रहे हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का आदर करना और कानून के तहत सभी समुदायों के साथ बराबरी से पेश आना लोकतांत्रिक सिद्धांत है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने बिना किसी अध्ययन के इस तरह का बयान देकर ये भी साबित किया है कि अब वहां पढ़ने लिखने वाले लोग नहीं बचे हैं। अमेरिका ये बयान उसकी पाक परस्ती को भी साबित करने के काफी है। सीएए को लेकर पाकिस्तान के पेट में अधिक दर्द है। जबकि सीएए कानून किसी की नागरिका छीनने के लिए नहीं है। हम हमारे देश में किस देश के किस व्यक्ति को नागरिका दें ये पूर्ण रूप से हमारा अधिकार है। इसके लिए पाक, चीन या अमेरिका को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मुमताज जहरा बलोच ने कहा- सीएए कानून का लागू होना हिंदू फासीवादी देश का भेदभावपूर्ण कदम है। यह कानून आस्था के आधार पर लोगों में भेदभाव पैदा करता है। सीएए इस गलत धारणा पर आधारित है कि मुस्लिम देशों में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किया जा रहा है और भारत अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षित देश है। जबकि सीएए का अध्ययन करने पर साफ पता चलता है कि ये कानून नागरिकता देने के बारे में नियम बनाता है न कि नागरिकता छीनने के बारे में। यह मानवीय गरिमा और मानवाधिकारों का समर्थन करता है। यह सबको साथ लेकर चलने की भारतीय परंपरा का प्रतीक है। सीएए अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के उन अल्पसंख्यकों को सुरक्षित पनाह देता है, जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ चुके हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने 11 मार्च को सिटिजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी सीएए का नोटिफिकेशन जारी किया था। इसके साथ ही यह कानून देशभर में लागू हो गया। सीएए को हिंदी में नागरिकता संशोधन कानून कहा जाता है। इससे पाकिस्तान, बांग्लादेश अफगानिस्तान से आए गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो गया। इसके तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को नागरिकता दी जाएगी। इन तीन देशों के लोग ही नागरिकता के लिए आवेदन कर सकेंगे। भारतीय नागरिकों से सीएए का कोई सरोकार नहीं है। संविधान के तहत भारतीयों को नागरिकता का अधिकार है। सीएए या कोई कानून इसे नहीं छीन सकता।

# अखिलेश यादव का 'एमवाई' खेल खराब करेगा मायावती का 'डीएम'

**मायावती की राजनैतिक सूझबूझ की आज भी कोई बराबरी नहीं है, जिन मायवती का पूर्व सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव से वर्षो तक 36 का आकड़ा रहा, कई बार मुलायम को मायावती ने सियासी मैदान पर धूल चटाई थी,उन मायावती को अखिलेश कभी हल्के में नहीं लेते यदि समाजवादी पार्टी का पुराना इतिहास वह पढ़ लेते। इंडी गठबंधन में बसपा को नहीं शामिल करने के लिये जमीन-आसमान एक किये हुए अखिलेश यादव को मायावती ने उन्हीं की पिच पर पटकनी देने का मन बना लिया है। यह पिच मुस्लिम वोट बैंक की है जिस पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव को काफी नाज है,लेकिन बसपा ने लोकसभा चुनाव के लिये सात में से पांच सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी उतार कर समाजवादी पार्टी के एमवाई (मुस्लिम-यादव) वोट बैंक में सेंधमारी की तैयारी कर ली है।**

संजय सक्सेना।

समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव बहुजन समाज पार्टी और उसकी सुप्रीमों मायावती के खिलाफ लगातार 'जहर' उगल रहे थे, जिसे बहनजी चुपचाप इकठा करती जा रही थीं, शायद वह सही समय का इंतजार कर रही होंगी। आज भले ही बसपा का जनाधार काफी घट गया है लेकिन इसका यह मतलब कतई नहीं है कि बसपा समाप्त पार्टी बन गई है। आज भले ही सपा-बसपा में भारी अदावत नजर आ रही हो लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव दोनों मिलकर लड़े थे। 2019 में संसद पहुंचने वाले उसके 10 सांसदों में तीन मुस्लिम थे। इस बार बसपा की रणनीति सपा-कांग्रेस गठबंधन को नुकसान पहुंचाने के संकेत दे रही है। बसपा सुप्रीमों की एक चाल ने 'सौ सुनार की, एक लुहार की' वाली कहावत चरितार्थ कर दी है।

दरअसल, पश्चिमी यूपी की मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर पार्टी ने इसी रणनीति के तहत प्रत्याशियों की घोषणा करनी शुरू कर दी है। अब तक घोषित किए गए उसके सात प्रत्याशियों में से पांच मुस्लिम हैं। हैरानी की बात यह है कि बसपा अपने किसी भी मौजूदा सांसद को टिकट देने के मूड में नहीं दिख रही है। फिलहाल पार्टी के साथ अपनी आस्था जताने वाले बिजनौर से सांसद मलूक नागर की जगह विजेंद्र सिंह को प्रत्याशी घोषित किया गया है। उनका मुकाबला रालोद के चंदन चौहान से होगा। यानी यहां जाट और गुर्जर मैदान में हैं, कांग्रेस-सपा का प्रत्याशी घोषित होना बाकी है। उधर,कांग्रेस के खेमे में जा रहे अमरोहा के सांसद दानिश अली की जगह डॉ. मुजाहिद हुसैन को प्रत्याशी बनाया गया है। सहारनपुर के बसपा सांसद हाजी फजलुर्रहमान को कांग्रेस टिकट दे सकती है, लिहाजा बसपा ने माजिद अली को प्रत्याशी घोषित कर दिया है। वहीं, पश्चिमी यूपी की मुजफ्फरनगर सीट पर दारा सिंह प्रजापति को बसपा ने प्रत्याशी घोषित किया है। इसी तरह मुरादाबाद में इरफान सैफी को, तो पीलीभीत में अनीस अहमद खां को प्रत्याशी घोषित किया गया है। कन्नौज सीट पर अकील अहमद पट्टा को प्रत्याशी बनाया गया है। इस सीट पर भाजपा के सुब्रत पाठक मैदान में हैं, जबकि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के भी यहां से चुनाव लड़ने की चर्चा है, जो उनके लिये खतरे की घंटी से कम नहीं है। इतना ही नहीं बसपा एनडीए में भी सेंधमारी कर रही है,जिससे लोकदल को बड़ा झटका लगा है। दरअसल रालोद के राष्ट्रीय महासचिव चौधरी विजेंद्र सिंह ने अचानक से पार्टी को लोकसभा चुनाव 2024 से पहले छोड़ कर सबको हैरान कर दिया है। इससे पहले वह लोकदल के प्रसार में जुटे हुए थे। उन्होंने लोकदल को छोड़कर बसपा को ज्वाइन कर लिया है। उन्होंने मंगलवार को बीएसपी में शामिल होने की घोषणा बिजनौर के कार्यकर्ता सम्मेलन में की। इस कार्यकर्ता सम्मलेन में बीएसपी के पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड प्रभारी शमशुद्दीन राइन ने चौधरी विजेंद्र सिंह के बीएसपी की सदस्यता लेने की घोषणा की। मायावती ने चौधरी विजेंद्र सिंह को बिजनौर लोकसभा प्रत्याशी बनाए जाने की घोषणा की है। उन्होंने आगे कहा कि बहन जी सबसे पहले बिजनौर सीट से जीत दर्ज करके संसद पहुंची थी। चौधरी विजेंद्र सिंह ने अपने अस्पतालों व शिक्षण संस्थानों के माध्यम से जनता की सेवा की है। जिसको देखते हुए बहन मायावती ने उन्हें बिजनौर लोकसभा प्रत्याशी बनाने का फैसला लिया है। एक दो दिन में बीएसपी चौधरी विजेंद्र सिंह को बिजनौर सीट से लोकसभा सीट का टिकट देने की घोषणा कर सकती है। बिजनौर के जिलाध्यक्ष दलीप कुमार ने यह जानकारी दी थी कि एक दो दिन में पार्टी प्रमुख बहन मायावती उन्हें लोकसभा टिकट दे देंगी। वहीं चौधरी विजेंद्र सिंह ने कहा कि किसान, मजदूर, गरीब सभी पिछड़ी जातियों समेत शोषित और वंचितों को उनका हक दिलाने का कार्य करेंगे।

चौधरी के बसपा की सदस्यता ग्रहण करने से पहले यहां बीजेपी-आएलडी गठबंधन की जीत पक्की समझी जा रही थी। दोनों ने गठबंधन के तहत रालोद विधायक चंदन चौहान को बिजनौर सीट से प्रत्याशी घोषित किया गया था। चौधरी विजेंद्र सिंह की नजर भी जाट वोटों को साधने की थी, जो कि लोकदल को जीत दिलाने के मकसद से कार्य कर रहे थे। लेकिन भाजपा के साथ गठबंधन के बाद इस सीट का समीकरण बदल जाने के कारण चौधरी विजेंद्र सिंह ने अपनी राह बदल ली और बीएसपी को ज्वाइन कर लिया। अब जब बीएसपी ने चौधरी विजेंद्र सिंह को बिजनौर सीट से प्रत्याशी बना दिया है तो वहां भाजपा-आरएलडी गठबंधन और बीएसपी के बीच चुनावी घमासान होने की संभावना है। कुल मिलाकर मायावती के मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट देने से बसपा को भले ही कोई फायदा न हो लेकिन इससे सपा को जरूर नुकसान हो सकता है। आजमगढ़ लोकसभा सीट के बीते उपचुनाव को देखें तो सपा के प्रत्याशी रहे धर्मेन्द्र यादव को केवल इसीलिए हार का सामना करना पड़ा था क्योंकि उनके सामने बसपा के मुस्लिम प्रत्याशी गुड्डू जमाली को टिकट मिल गया था। इस उपचुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी की जीत हुई थी।

अब जरूर जमाली सपा में हैं और पार्टी ने उन्हें विधान परिषद सदस्य के लिये चुन लिया है। बता दें कई चुनावों में ये देखने को मिलता रहा है कि बसपा के मुस्लिम प्रत्याशी उतारने से सपा का एम-वाई फार्मूला कहीं हद तक असफल हो जाता है। बसपा के मुस्लिम प्रत्याशी सपा की जीत के लिए एक बड़ा रोड़ा बन जाते है। मायावती अपनी रणनीति के अनुसार मुस्लिमों पर फोकस करती रही हैं. वो लगतार ये समझाने का प्रयास करती हैं, कि दलित और मुस्लिम एक साथ आजाएं तो बीजेपी को हराया जा सकता है। पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो बसपा का सिर्फ एक ही प्रत्याशी जीता था। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में बलिया जिले की रसड़ा सीट से उमाशंकर सिंह ने जीत हासिल की थी। अन्य सभी विधानसभा सीटों पर बसपा को हार का सामना करना पड़ा था। अब इस लोकसभा चुनाव में मुस्लिम चेहरों पर मायावती ने एक बार फिर दांव लगाया है।

## आज का राशिफल

हमारे अनुभवी ज्योतिषियों की टीम के अनुसार आप कई विविध लक्ष्यों को पूरा करेंगे। क्या आप यह जानना चाहते है कि आपके जीवन के ऐसे कौनसे क्षेत्र है, जहां आपके सितारे बुलंद रहेंगे और दूसरी तरफ, आपको किस बातों से सावधान रहना चाहिए। हम न सिर्फ हमारे काम में और जटिल मुद्दों को सुलझाते वक्त सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करेंगे, बल्कि पारिवारिक संबंधों में भी, जहां यह स्थानान्तरण हमें संतोष और बातचीत में लाभ प्रदान करेगा

**मेष**
आपको अपने उग्र स्वभाव और जिद्दी व्यवहार पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। परिश्रम के बाद निर्धारित सफलता नहीं मिलने से मन में खिन्नता रहेगी। शारीरिक स्वास्थ्य भी कमजोर रहेगा। यात्रा के लिए योग्य समय नहीं है।

**वृष**
आज कोई भी खतरनाक कदम आपको कठिनाई में डाल सकता है। नौकरी-धंधे में तकलीफ और अवरोध उत्पन्न होंगे। ऑफिस में अधिकारियों के साथ वाद-विवाद में पड़ने से हानि होने की आशंका रहेगी।

**मिथुन**
सरकारी काम में सफलता या लाभ मिलेगा। संतान के पीछे पैसे खर्च होंगे। कलाकारों एवं खिलाड़ियों के लिए अपनी प्रतिक्षा दर्शाने के लिए उत्तम समय है। दिन की शुरुआत से ताजगी और स्फूर्ति का अनुभव करेंगे।

**कर्क**
स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी शिकायत रहेगी। वैवाहिक जीवन में मधुरता का अनुभव होगा। सरकारी कामकाज शीघ्रता से पूरे होंगे। शारीरिक और मानसिक चिंता में रहेंगे। इगो के कारण किसी के साथ झगड़ा हो सकता है। आकस्मिक धन खर्च होगा। संतान को लेकर चिंता रहेगी।

**सिंह**
आज मन में थोड़ी हताशा रह सकती है। परिवार में सदस्यों के साथ गलतफहमी या मनमुटाव होगा। इगो से किसी की भावनाओं को चोट पहुंचेगी। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। आज आपका काफी धन खर्च होगा।

**कन्या**
आपके सभी काम सरलता से पूरे होंगे। गृहस्थ जीवन में आनंद और संतोष का अनुभव होगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। समाज में मान-सम्मान मिलेगा। अधिकारियों और बुजुर्गों की कृपादृष्टि रहेगी। शारीरिक तथा मानसिक रूप से चिंता में रहेंगे।

**तुला**
किसी भी मामले में बिना विचारे काम से हानि ही होगी। सरकारी काम में सफलता मिलेगी। आज आपकी कार्य सफलता में दृढ़ मनोबल और आत्मविश्वास की भूमिका होगी। विद्यार्थी पढ़ाई में रुचि बनाए रख सकेंगे।

**वृश्चिक**
आज आपके लिए नकारात्मक विचारों से दूर रहने और खान-पान पर ध्यान देने की जरूरत है। चिकित्सा के पीछे खर्च होने की संभावना है। व्यापार में भागीदारों के साथ मतभेद बढ़ेंगे। क्रोध और आवेश पर नियंत्रण रखना पड़ेगा।

**धनु**
असंतोष की भावना से मन चिंतित रहेगा। आत्मविश्वास तथा त्वरित निर्णय लेकर काम में आगे बढ़ सकेंगे। सामाजिक मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। वाणी, व्यवहार में उग्रता तथा किसी के साथ इगो का टकराव होने की संभावना है।

**मकर**
दांपत्य जीवन में परेशानी आ सकती है। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य खराब होगा। अधीनस्थ व्यक्ति तथा नौकरवर्ग से परेशानी का अनुभव होगा। गृहस्थ जीवन में सुख और आनंद की प्राप्ति होगी। आय वृद्धि का योग है।

**कुंभ**
ऑफिस, व्यवसाय के क्षेत्र में अनुकूल वातावरण रहेगा। पदोन्नति मिलने के योग हैं। पारिवारिक सदस्य तथा मित्र मंडल के साथ खुश रहेंगे। व्यापारी वर्ग को लाभ होगा। उत्तम वैवाहिक सुख प्राप्त होने की संभावना है।

**मीन**
भाग्यवृद्धि के अवसर आएंगे। तेजी से बदलते हुए विचार आपको उलझनपूर्ण स्थिति में रखेंगे। नए काम का आरंभ कर सकेंगे। मित्रों सगे- स्नेहियों और पड़ोसियों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। आर्थिक दृष्टि से आपको लाभ होने का योग है।

## आज का इतिहास

### 16 मार्च की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

- फ्रांस के राजा लुईस चौदहवें ने 1690 में आयरलैंड में सेना भेजी।
- अमृतसर समझौते के मुताबिक कश्मीर का आधिपत्य 1846 में जम्मू के हिंदू राजा गुलाब सिंह के अधीन कर दिया गया।
- चेकोस्लोवाकिया पर जर्मनी ने 1939 में कब्जा किया।
- इराक और सोवियत संघ ने 1959 में आर्थिक एवं तकनीक समझौते पर हस्ताक्षर किये।
- अमेरिका ने 1966 में मानवयुक्त अंतरिक्ष यान जेमिनी 8 लांच किया।
- आठ सालों तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और 13 वर्षों तक लेबर पार्टी के नेता रहे, हैरल्ड विल्सन ने 1976 में त्यागपत्र देकर सबको चौंका दिया था।
- अमेरिका ने 1978 में नेवादा में परमाणु परीक्षण किया।
- रूस ने 1982 में पश्चिम यूरोप में नए परमाणु मिसाइलों की तैनाती रोकने की घोषणा की।
- मिस्र में चिपोज के पिरामिड में 1989 में 4400 साल पुरानी ममी मिली।
- नासा अंतरिक्ष यात्री नॉर्मन रूसी 1995 में अंतरिक्ष स्टेशन मीर का दौरा करने वाले पहले अमेरिकी बने।
- चीनी राष्ट्रपति जियांग जेमिन 1998 में अगले कार्यकाल के लिए पुन: राष्ट्रपति निर्वाचित।
- ग्रीन स्मिथ 2003 में दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेट कप्तान बने।
- रूस में 2004 में नौ मंजिला इमारत में विस्फोट, 21 मरे।
- संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कोफ़ी अन्नान ने 2005 में सुपाचयी पानिचपकड़ी को अंकटाड का नया अध्यक्ष नामांकित किया।
- सन 2006 में चुनाव के तीन महिने बाद ईराक की नयी संसद ने शपथ ग्रहण की।
- दक्षिण अफ्रीका के हर्शेल गिब्स ने 2007 में एक ओवर में छह छक्के लगाकर विश्व रिकार्ड बनाया।
- परवेज मुशर्रफ ने 2008 में पाकिस्तान में सजा-ए-मौत पा चुके भारतीय नागरिक सरबजीत सिंह के डेथ वारंट पर दस्तखत किये।
- भारत के मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर 2012 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 100 शतक बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने।
- पाकिस्तान के रावलपिंडी में 2013 में हुए बस दुर्घटना में लगभग 25 सैनिकों की जान गयी।
- यूक्रेन छोड़कर रूस में शामिल होने के पक्ष में क्रीमिया के लोगों ने 2014 में मतदान किया।

### 16 मार्च को जन्मे व्यक्ति

- इंदौर के होल्कर वंश का प्रवर्तक मल्हारराव होल्कर का 1693 में जन्म।
- गांधी जी के अनुयायी स्वतन्त्रता सेनानी पोट्टि श्रीरामुलु का 1901 में जन्म।
- भारत के जाने-माने शिक्षाविद और हिन्दी साहित्यकार अम्बिका प्रसाद दिव्य का 1906 में जन्म।
- हिन्दी सिनेमा के प्रसिद्ध खलनायक तथा फ़िल्म निर्माता दयाकिशन सप्रू का 1916 में जन्म।
- अमेरिकी टेलीविजन पटकथा लेखक और नाटककार हार्डिंग लेमेयका 1922 में जन्म।

### 16 मार्च को हुए निधन

- 1947 में प्रसिद्ध कवि, साहित्यकार अयोध्यासिंह उपाध्याय का निधन।
- 1999 में फैंटम जैसे हास्य चरित्र के जनक लियोन ली फाक का निधन।

## विशेष आलेख

# रेवड़ी संस्कृति को रोकने का समय, मुफ्त सुविधाओं की जगह आय बढ़ाने पर दिया जाए

आर के सिन्हा।

आगामी लोकसभा चुनावों की घोषणा शीघ्र ही होने वाली है। इस सिलसिले में विभिन्न राजनीतिक दल अपनी चुनावी रणनीति और उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप देने में लगे हैं। इसी के साथ उन्होंने लोकलुभावन घोषणाएं करना भी शुरू कर दिया है। यह मानकर चलिए कि आने वाले दिनों में राजनीतिक दल जनता को लुभाने के लिए बहुत कुछ मुफ्त में देने का वादा करेंगे। राहुल गांधी ने नारी न्याय गारंटी के नाम पर ऐसी कई घोषणाएं कर भी दी हैं। उन्होंने हर गरीब महिला को सालाना एक लाख रुपये देने का वादा किया है। उन्होंने इस तरह की घोषणाएं पिछले लोकसभा चुनाव के समय भी की थीं, लेकिन उनसे जनता प्रभावित नहीं हुई। इस पर विचार किया जाना चाहिए कि मुफ्त बिजली, पानी और दूसरी तमाम चीजें देना कहां तक उचित है और वह भी चुनाव जीतने के लिए? लोकसभा और विधानसभा चुनावों में मुफ्त की घोषणाएं करना कोई नया चलन नहीं है। इस चलन पर बहस होती रहती है और इसके विरोध में कई स्वर भी सुनाई देते रहे हैं, पर होता कुछ नहीं है। अपने देश में रेवड़ियां बांटने का वादा और फिर उन पर जैसे-तैसे और अक्सर आधे-अधूरे ढंग से अमल का दौर चलता ही रहता है। लोकलुभावन वादों को पूरा करने की लागत अंतत: मतदाताओं को खासकर करदाताओं को ही वहन करनी पड़ती है-अक्सर करों अथवा उपकरों के रूप में। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तेलंगाना विधानसभा चुनाव के समय मुफ्त रेवड़ियां देने के मुद्दे को उठाते हुए कहा था कि कई राज्यों ने अपनी वित्तीय स्थिति की अनदेखी करते हुए मुफ्त की सुविधाएं देने का वादा कर दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने भी मुफ्त रेवड़ियां बांटने के चलन पर गंभीर चिंता जताई थी। नीति आयोग के साथ रिजर्व बैंक भी मुफ्त की रेवड़ियों पर आपत्ति जता चुका है, लेकिन राजनीतिक दलों पर कोई असर नहीं। कई बार तो वे अपात्र लोगों को भी मुफ्त सुविधाएं देने के वादे कर देते हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी कुछ समय पहले उन दलों को आड़े हाथों लिया था, जो वोट लेने के लिए मुफ्त की रेवड़ियां देने के वादे करते हैं। उनका कहना था कि रेवड़ी बांटने वाले कभी विकास के कार्यों जैसे रोड, रेल नेटवर्क आदि का निर्माण नहीं करा सकते। वे अस्पताल, स्कूल और गरीबों के घर भी नहीं बनवा सकते।

रेवड़ी संस्कृति अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के साथ ही आने वाली पीढ़ियों के लिए घातक भी साबित होती है। इससे मुफ्तखोरी की संस्कृति जन्म लेती है। मुफ्त की सुविधाएं पाने वाले तमाम लोग अपनी आय बढ़ाने के जतन करना छोड़ देते हैं। दिल्ली में उन महिलाओं को भी डीटीसी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी गई है, जिन्हें इस तरह की सुविधा की जरूरत नहीं। आधी आबादी को मुफ्त यात्रा की सुविधा देने से दिल्ली में डीटीसी को हर साल 15 करोड़ रुपये तक का नुकसान होगा। इस राशि का उपयोग दिल्ली के इन्फ्रास्ट्रक्चर पर किया जा सकता है। अब चूंकि लोकसभा के चुनाव करीब हैं तो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि यदि आगामी आम चुनाव में सभी सातों सीटें आप और कांग्रेस के उम्मीदवारों को मिलीं तो वह 15 दिन के अंदर सबका पानी का बिल माफ कर देंगे। आखिर इस तरह की रेवड़ियां बांटने का क्या मतलब? केजरीवाल पानी के बिल माफ करने का वादा करते हुए यह भूल गए कि दिल्ली में लाखों लोगों को अब भी प्राइवेट टैंकरों से पानी खरीद कर गुजारा करना पड़ता है। जब मुफ्त पानी, बिजली आदि दी जाने लगती है तो उसका दुरुपयोग भी होने लगता है। अफसोस होता है कि हमारे देश में चुनाव में मुफ्त की सुविधाएं बांटना सामान्य हो गया है। तमिलनाडु से उपजा चलन अब सारे देश में फैल गया है। यदि कोई नेता या राजनीतिक दल गरीबों को कोई सुविधा मुफ्त देने का वादा कर रहा है तो उसे यह भी बताना चाहिए कि वह उसके लिए धन कहां से लाएगा? अनेक अर्थशास्त्री मुफ्त उपहार बांटकर लोगों के वोट खरीदने की खतरनाक प्रवृत्ति के प्रति आगाह कर चुके हैं, लेकिन उनकी चिंताओं से नेता बेपरवाह हैं। वे यह देखने को तैयार ही नहीं कि अनाप-शनाप चुनावी वादों को पूरा करने की कीमत क्या होती है और उनसे आर्थिक सेहत पर कितना बुरा असर पड़ता है। चुनाव के समय किए गए वादों का राजकोषीय प्रभाव सरकार बनने के लगभग 12-18 महीनों के बाद ही महसूस किया जा सकता है। चूंकि यह पक्का है कि राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्रों में लोकलुभावन वादे करेंगे ही, इसलिए चुनाव आयोग को अपने स्तर पर कुछ करना चाहिए। इसी के साथ मतदाताओं को भी इस प्रवृत्ति से परहेज करना होगा। उन्हें शिक्षा, सेहत और रोजगार जैसे जरूरी सवालों पर सर्वाधिक ध्यान देना चाहिए। इससे ही देश में एक स्वस्थ चुनावी संस्कृति का निर्माण होगा।

# चांद दिलाने का वायदा करने वाली पार्टियों पर लगे अंकुश

इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर विभिन्न विषयों पर उभरने वाले वीडियो की भरमार है, ऐसे बहुत कम वीडियो हैं जो आपको विचारोत्तेजक लगते हैं और आपको चौंका देते हैं। ऐसा ही एक वीडियो हाल ही में एक कुली द्वारा एक छोटे मीडिया आऊटलैट को दी गई प्रतिक्रिया का था। सामान्य कुली की लाल शर्ट पहने हुए व्यक्ति के साथ यह वीडियो किसी नाटक का नहीं लग रहा था। कुली से प्रधानमंत्री की हालिया घोषणा के संबंध में एक सवाल पूछा गया था कि मुफ्त राशन योजना को अगले 5 साल के लिए बढ़ाया जा रहा है। इस योजना के अनुमानित 80 करोड़ लाभार्थी हैं जो हमारी आबादी के आधे से थोड़ा कम है। कुली ने एक उचित मुद्दा उठाया। उसने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारी आजादी के 75 साल बाद भी इतनी बड़ी आबादी को मुफ्त राशन देना पड़ रहा है। यह आबादी को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए काफी लंबी अवधि थी, ताकि उन्हें जीवित रहने के लिए मुफ्त राशन पर निर्भर न रहना पड़े। उसने इस स्थिति के लिए किसी विशेष सरकार या पार्टी को दोषी नहीं ठहराया लेकिन वह स्पष्ट रूप से सच कह रहा था। और फिर उसने एक और महत्वपूर्ण बात कही। उसने कहा कि यह भी उतना ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस योजना को 5 साल तक बढ़ाना पड़ा क्योंकि ऐसा लगता है कि सरकार ने स्वीकार कर लिया है कि वह अगले 5 वर्षों में ऐसा करने में सक्षम नहीं होगी। उसने आगे कहा कि शायद प्रधानमंत्री को यह घोषणा करनी चाहिए थी कि मुफ्त राशन देने की कोई आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए पर्याप्त उपाय किए जाएंगे जब उन्हें जीवित रहने के लिए मुफ्त राशन की आवश्यकता नहीं होगी।

कम से कम इतना तो किया ही जा सकता है कि अधिक नौकरियां और अन्य अवसर पैदा करके ऐसे लाभार्थियों की संख्या कम की जाए। वास्तव में इसकी आवश्यकता है और यह हमारे समाज और राष्ट्र पर एक खराब प्रतिबिम्ब है कि हम गरीबों के जीवन स्तर में सुधार करने में विफल रहे हैं। जैसा कि कई सर्वेक्षणों से पता चलता है कि अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ती जा रही है। महत्वपूर्ण आम चुनावों के करीब आने के साथ, राजनीतिक दल सामाजिक कल्याण उपायों की आड़ में सभी प्रकार की मुफ्त सुविधाओं की घोषणा कर रहे हैं। यह कोई नई घटना नहीं है लेकिन हर चुनाव के साथ ऐसी गतिविधियों का दायरा और आकार बढ़ता जा रहा है।